Volume: 3 Issue: 7 Pages: 73-76

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में प्रवासन पैटर्न और आजीविका परिणामों पर नीतिगत हस्तक्षेपों का प्रभाव

[*1] शुभम भट्ट एंव [2]डॉ प्रकाश लखेड़ा

[*1] शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड, भारत।

[2] सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 5.231
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 18/June/2024
Accepted: 20/July/2024

***Corresponding Author**
शुभम भट्ट
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड, भारत।

सारांश:
भारत के उत्तराखंड राज्य का पिथौरागढ़ जिला पर्यटन की जटिल और विविध विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह अध्ययन इस क्षेत्र में यात्रा पैटर्न और आजीविका परिणामों पर नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभावों की जांच करता है। यह नीति, पर्यटन और विकास के बीच जटिल संबंधों की गहरी समझ हासिल करने के लिए विभिन्न डेटा स्रोतों का उपयोग करता है। यह अध्ययन भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जनसंख्या के प्रवासन पैटर्न और आजीविका परिणामों पर नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभावों की जांच करता है। इस पहाड़ी क्षेत्र में प्रवास के कारकों और परिणामों को समझने के लिए जांच में सरकारी रिकॉर्ड, घरेलू सर्वेक्षण और गुणात्मक साक्षात्कार जैसे कई डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष बताते हैं कि हालांकि बुनियादी ढांचे और आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने को लक्षित करने वाली नीतियों ने कुछ अनुकूल परिणाम दिए हैं, लेकिन उन्होंने पलायन को बढ़ावा देने वाले बुनियादी संरचनात्मक कारकों से पर्याप्त रूप से नहीं निपटा है। ये कारक क्षेत्र के भौगोलिक एकांत, सीमित आर्थिक विविधता और आवश्यक सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच से उत्पन्न होते हैं। अध्ययन प्रवासन नीति के लिए एक व्यापक और स्थितिजन्य दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर देता है जो प्रवासियों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट कठिनाइयों पर विचार करता है।

मुख्य शब्द: पलायन, बुनियादी संरचनात्मक, नीतिगत हस्तक्षेपों, सामाजिक कल्याण

प्रस्तावना:

भारतीय हिमालय में स्थित उत्तराखंड में, खास तौर पर इसके पहाड़ी इलाकों से, बड़े पैमाने पर पलायन का लंबा इतिहास रहा है। यह समस्या कुछ क्षेत्रों में आर्थिक अविकसितता और जीविकोपार्जन के सीमित अवसरों से निकटता से जुड़ी हुई है, जो निवासियों को रोजगार और बेहतर जीवन स्थितियों की तलाश कहीं और करने के लिए मजबूर करती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समय-समय पर कई नीतिगत हस्तक्षेप लागू किए गए हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास और लक्षित सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। हालाँकि, इस बात पर बहस जारी है कि क्या ये रणनीतियाँ पलायन को कम करने और पर्वतीय समुदायों की भलाई में सुधार करने में प्रभावी हैं। उत्तराखंड के पूर्वी भाग में स्थित पिथौरागढ़ जिला इन गतिशीलताओं का एक प्रमुख उदाहरण है। यह अध्ययन इस क्षेत्र में जनसंख्या पलायन पैटर्न और आजीविका परिणामों पर नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभाव की जाँच करता है। यह नीति, पलायन और विकास के बीच जटिल संबंधों की व्यापक समझ हासिल करने के लिए कई डेटा स्रोतों का उपयोग करता है। अध्ययन पिथौरागढ़, उत्तराखंड में पलायन की जटिल और विविध विशेषताओं और पलायन के अंतर्निहित कारणों से निपटने में वर्तमान नीतिगत हस्तक्षेपों की सीमित प्रभावकारिता पर प्रकाश डालता है। निष्कर्ष प्रवास नीति के लिए एक गहन और संदर्भ-विशिष्ट दृष्टिकोण को लागू करने के महत्व पर जोर देते हैं, जो पर्वतीय समुदायों द्वारा अनुभव की जाने वाली विशेष चुनौतियों से निपटता है और तेजी से वापसी करने के लिए उनकी अंतर्निहित क्षमताओं और लचीलेपन का उपयोग करता है।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आबादी का पलायन एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक चिंता बन रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य इस पर्वतीय क्षेत्र में पलायन के चालकों और परिणामों को व्यापक रूप से समझना और नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभाव का विश्लेषण करना है। पिथौरागढ़ अपनी भौगोलिक विशेषताओं और आर्थिक कठिनाइयों के परिणामस्वरूप प्रवास की एक जटिल प्रणाली का एक घटक है। इस क्षेत्र के निवासियों के सामने आने वाली प्राथमिक चुनौतियों में सीमित आर्थिक संभावनाएँ, चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय

परिस्थितियाँ और महत्वपूर्ण सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता शामिल हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए, बुनियादी ढाँचे में सुधार और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन जैसी कई नीतिगत पहलों को लागू किया गया है। हालाँकि, प्रवासी पैटर्न पर इन नीतियों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए आगे की जाँच और स्पष्ट निष्पादन आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र उत्तराखण्ड का संक्षिप्त परिचय

उत्तराखण्ड भौगोलिक रूप से भारत के उत्तर भू भाग में स्थित है। जिसका विस्तार 280 43' से 31027' उत्तरी अक्षांश तथा 770 34' से 810 02' पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी है, जोकि भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.69 प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का 18 वां राज्य है। धरातलीय विन्यास, स्तर शैलक्रम तथा उच्चावच स्वरूपों के आधार पर राज्य को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यथा गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र तथा वृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाऐं नेपाल तथा चीन तथा अन्त्र राज्यीय सीमाऐं हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा हरियाणा से मिलती हैं। राज्य बनने के उपरान्त राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से गढ़वाल मण्डल तथा कुमाऊँ मण्डल के रूप में विभक्त किया गया है।

भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पिथौरागढ़ जिला अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और तिब्बत से निकटता के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न मार्गों से तिब्बत के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और हिमालय में विस्मयकारी सौंदर्य प्रदान करता है। इस जिले का गठन 1960 में चीनी हमले के बाद हुआ था और यह समुद्र तल से 1645 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मध्य हिमालय के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी दिशा में नेपाल से सटा हुआ है। जिले का कुल क्षेत्रफल 7,217.7 वर्ग किलोमीटर है और इसमें अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और चमोली जिलों की राष्ट्रीय सीमाएँ शामिल हैं। पर्यटक चंडाक, थल केदार, गंगोलीहाट, पाताल भुवनेश्वर, बेरीनाग, डीडीहाट, मुनस्यारी, धारचूला और जौलजीबी जैसे मनोरम स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। यह जिला मिलम, रालम और नामिक ग्लेशियर के लिए ट्रेक के साथ-साथ कैलास मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, नारायण स्वामी आश्रम और जौलजीबी के लिए कई आधार शिविरों का भी घर है। [1]

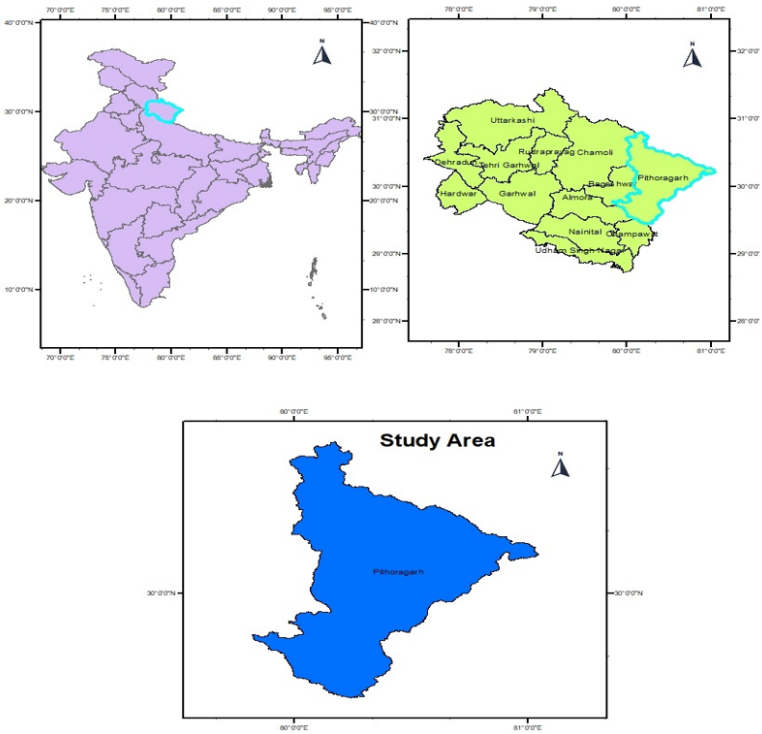

चित्र 1: अध्ययन क्षेत्र पिथौरागढ़

शोध प्रविधि और आकड़ों का संकलन

यह अध्ययन मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा स्रोतों को शामिल किया गया है, ताकि पिथौरागढ़ क्षेत्र में प्रवासी पैटर्न और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों की अधिक व्यापक समझ प्रदान की जा सके। अध्ययन के मात्रात्मक पहलू में जिले से पलायन में प्रवृत्तियों और पैटर्न का पता लगाने के लिए जनगणना रिकॉर्ड और प्रवास सर्वेक्षण जैसे सरकारी स्रोतों से प्राप्त द्वितीयक डेटा का विश्लेषण करना शामिल है। गुणात्मक घटक में स्थानीय सरकारी अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं और प्रवासी परिवारों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ गहन साक्षात्कार आयोजित करना शामिल है। इन साक्षात्कारों का उद्देश्य प्रवास से संबंधित वास्तविक अनुभवों, उद्देश्यों और कठिनाइयों की गहरी समझ हासिल करना है। इन डेटा स्रोतों को कई कोणों से संयोजित और विश्लेषित किया जाता है, ताकि इस बारे में गहन ज्ञान प्राप्त किया जा सके कि नीति हस्तक्षेप क्षेत्र में प्रवास और आजीविका परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी विकास खंड के बूंगा गाँव, डीडीहाट विकास खंड के हटपर्थ गाँव, धारचूला विकास खंड के धारचूला देहात, बेरीनाग विकास खंड के गरारु गाँव व कनालीछीना विकास खंड के सतगढ़ गाँव में आयोजित किया गया था. तथा स्थानीय लोगों की राय के अनुसार प्राप्त आकड़ों व जानकारी का विश्लेषण किया गया है है।

पिथौरागढ़ की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध स्थलाकृति के लिए जाना जाता है, अपने ऊबड़-खाबड़ भूभाग के कारण कृषि और बुनियादी ढांचे में चुनौतियों का सामना करता है। अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो जीविका के लिए वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है। पिथौरागढ़ में पलायन आर्थिक अवसरों

की कमी और महत्वपूर्ण सेवाओं की कमी के कारण होता है। पलायन में योगदान देने वाले कारकों में अपर्याप्त नौकरी की संभावनाएँ, वर्षा आधारित कृषि के कारण कम कृषि उत्पादकता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक अपर्याप्त पहुँच जैसे सामाजिक कारण, पहाड़ी क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पर्यावरणीय कारण और भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं।

पिथौरागढ़ जिले में पलायन को प्रबंधित करने और स्थानीय आजीविका को बढ़ाने के लिए सरकारी कार्रवाई की गई है। पहलों में बुनियादी ढाँचा विकास, मनरेगा जैसी सामाजिक कल्याण योजनाएँ, कृषि सुधार और शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार शामिल हैं। बुनियादी ढाँचा विकास का उद्देश्य सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था में सुधार करना है, जबकि मनरेगा जैसी सामाजिक कल्याण योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। कृषि सुधारों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए समकालीन पद्धतियों और किसान प्रशिक्षण का प्रसार शामिल है।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आजीविका पर पलायन के प्रभाव में योगदान देने वाले मुख्य कारण विकास की अनुपस्थिति, सीमित नौकरी की संभावनाएं, चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियां और लोगों के इस क्षेत्र को छोड़ने का ऐतिहासिक चलन है । [2] कोविड-19 महामारी ने मुद्दों को और बदतर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप रिवर्स माइग्रेशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई क्योंकि व्यक्ति नौकरी की चिंताओं के कारण अपने गृहनगर लौट गए । [3] महामारी से प्रेरित रिवर्स माइग्रेशन ने श्रम के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करने और ग्रामीण विकास और कृषि संवर्द्धन के उद्देश्य से सरकारी रणनीतियों की समीक्षा करने का मौका दिया है ताकि पलायन के मुद्दे से निपटा जा सके । [4] इसके अलावा, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों के लोगों का पलायन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, बेरोजगारी और आवश्यक सुविधाओं के अभाव से जुड़ा हुआ है। इसका ग्रामीण पर्यावरण और कृषि प्रथाओं पर और अधिक प्रभाव पड़ता है । [5-6]

शोध परिणाम और चर्चा

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि बुनियादी ढांचे के विकास के प्रभाव बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयासों ने कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिए हैं। सड़कों और बिजली की बढ़ी हुई पहुंच ने आंशिक रूप से वाणिज्यिक विकास को बढ़ावा दिया है। फिर भी, इन प्रयासों ने सीमित रोजगार के अवसरों और कृषि पद्धतियों की कम दक्षता जैसे प्रवास को बढ़ावा देने वाले बुनियादी कारकों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव पर अध्ययन से ज्ञात हुआ कि मनरेगा जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण रोजगार में मामूली वृद्धि की है, लेकिन उन्होंने अपना प्रभाव सीमित कर दिया है। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को दिए जाने वाले काम के अवसर अस्थायी प्रकृति के हैं और पलायन को रोकने के लिए अपर्याप्त हैं। कृषि सुधारों के विषय में स्थानीय लोगों ने बताया कि कृषि में आधुनिक पद्धतियों और शैक्षिक पहलों के कार्यान्वयन ने कई किसानों की दक्षता में वृद्धि की है, फिर भी इन प्रगति का प्रसार सीमित है। साथ ही अध्ययन क्षेत्र में पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ और प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित पहुँच कृषि परिवर्तनों की प्रभावकारिता में बाधा डाल रही हैं।

शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवा सुधारों के प्रभाव शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ी हुई उपलब्धता के परिणामस्वरूप कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास में कमी आई है क्योंकि अब व्यक्तियों को अपने गाँवों के अंदर बेहतर सेवाओं तक पहुँच प्राप्त है। हालाँकि, इस सुधार का कार्यान्वयन व्यापक नहीं रहा है, जिसके कारण कई समुदाय बेहतर सेवाओं की तलाश में स्थानांतरित हो रहे हैं।

प्रवास के सामाजिक-आर्थिक परिणाम

प्रवास ने पिथौरागढ़ के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को काफी प्रभावित किया है, जिससे कृषि उत्पादकता, आय और सामाजिक संरचना में गिरावट आई है। पुरुषों के प्रवास के कारण श्रमिकों की कमी हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप कई परिवारों, विशेष रूप से कृषि पर निर्भर लोगों की ग्रामीण आय में कमी आई है। आर्थिक गतिविधि में गिरावट ने स्थानीय बाजारों के संचालन को भी कम कर दिया है। पिथौरागढ़ की सामाजिक संरचना बदल गई है, पुरुषों के प्रवास के कारण महिलाओं की भूमिका और जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, और अब महिलाओं को बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद, प्रवास के मूल कारणों को संबोधित नहीं किया जा रहा है, जिसमें सीमित रोजगार के अवसर, अपर्याप्त कृषि उत्पादकता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना शामिल है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती उपलब्धता के बावजूद, कई गांवों को अभी भी इन सेवाओं तक पहुँचने के लिए स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जो इन सेवाओं की बढ़ी हुई क्षमता और उपलब्धता की आवश्यकता को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त, जनसंख्या वृद्धि पर प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव के कारण इन आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्नत आपदा प्रबंधन और पुनर्वास रणनीतियों की आवश्यकता होती है।

नीतिगत हस्तक्षेप के लिए उपाय

पिथौरागढ़ जिले में प्रवास को नियंत्रित करने और आजीविका परिणामों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नीतिगत उपाय सुझाए गए हैं:

1. **स्थायी रोजगार संभावनाओं की स्थापना:** ग्रामीण समुदायों को दीर्घकालिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योगों और सेवा क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्थानीय स्तर पर उद्योगों की स्थापना से रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
2. **कृषि सुधारों को सर्वव्यापी रूप से अपनाना:** कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों और उपकरणों का व्यापक प्रसार आवश्यक है। किसानों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए।
3. **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि:** ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना आवश्यक है। स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के साथ-साथ इन सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होनी चाहिए।
4. **भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक**: आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बेहतर आपदा प्रबंधन और पुनर्वास योजनाओं का कार्यान्वयन आवश्यक है।
5. **स्थानीय भागीदारी और नियोजन को बढ़ाना:** नीतिगत पहलों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। ग्रामीण निवासियों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ तैयार और क्रियान्वित की जानी चाहिए।
6. **माइक्रोफाइनेंस के विकास को सुगम बनाना और उद्यमिता को बढ़ावा देना:** ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रोफाइनेंस और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहल स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह पहल समुदायों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सुगम बनाएगी और प्रवास की आवश्यकता को कम करेगी।
7. **जलवायु परिवर्तन की घटना और पर्यावरण का संरक्षण:** जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और पर्यावरण की रक्षा के

उपायों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई को लागू करना महत्वपूर्ण है।

8. **समुदायों के विकास और सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम:** ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक वृद्धि को सुगम बनाने के लिए सामुदायिक विकास पहलों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और सामाजिक कल्याण से संबंधित गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए।

साथं ही यह अध्ययन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पलायन में योगदान देने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण कारकों का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि अविकसितता और रोजगार के अवसरों की कमी इस क्षेत्र को परेशान करती है, जिससे स्थानीय लोगों को कहीं और बेहतर अवसर तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कठिन पर्यावरणीय कारक, जैसे चुनौतीपूर्ण रहने की स्थिति, प्राकृतिक आपदाएँ और सीमित कृषि उत्पादन, लोगों के पलायन में योगदान करते हैं। किसी क्षेत्र से ऐतिहासिक पलायन के रुझान भी पलायन को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं। स्थायी पलायन पैटर्न ने एक आवर्ती चक्र का निर्माण किया है जो वर्तमान में जनसंख्या आंदोलनों को आकार देना जारी रखता है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव: महामारी के कारण नौकरी की अनिश्चितताओं के कारण अपने गाँवों में लौटने वाले व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, जिससे सामाजिक-आर्थिक प्रभावों और सरकारी उपायों का मूल्यांकन करने का अवसर मिला। सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ, जैसे उच्च बेरोज़गारी दर और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं का अपर्याप्त प्रावधान, पलायन की समस्या को और बदतर बना देता है, जिसका ग्रामीण पर्यावरण और कृषि प्रथाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन कठिनाइयों से निपटने के लिए, पिथौरागढ़ में पलायन को कम करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थायी समाधानों को लागू करना और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि यद्यपि नीतिगत हस्तक्षेपों का पिथौरागढ़ जिले के निवासियों पर कुछ लाभकारी प्रभाव पड़ा है, लेकिन वे पलायन के अंतर्निहित कारणों से निपटने में पर्याप्त नहीं रहे हैं। बड़े पैमाने पर पलायन का निरंतर प्रचलन, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से, इस क्षेत्र में पलायन प्रबंधन के लिए अधिक व्यापक और अनुरूप दृष्टिकोण की आवश्यकता को दर्शाता है। पलायन के मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, नीति निर्माताओं को एक व्यापक दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता है जो आर्थिक विविधीकरण, मानव पूंजी में निवेश और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा उपायों को जोड़ता है। हमें इसे एक विकेंद्रीकृत, भागीदारी रणनीति के साथ जोड़ना चाहिए जो स्थानीय समुदायों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए सशक्त बनाता है। उत्तराखंड में पर्वतीय लोगों के लिए टिकाऊ और उचित आजीविका की संभावनाओं को स्थापित करने के लिए, सरकार को इस क्षेत्र में प्रवासी प्रवृत्तियों को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय तत्वों के बीच जटिल संबंधों से निपटना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर गांवों के लिए परियोजनाएं विकसित करें। ग्रामीण विकास के लिए सभी विभागीय योजनाओं का समन्वय करें। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए ठोस उपाय लागू करें। माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करें। सुनिश्चित करें कि गांव की विकास योजनाओं में स्थानीय निवासियों की भागीदारी हो। प्रवासियों को घर लौटने के लिए प्रेरित करने के लिए ठोस योजनाएं बनाएं।

References

1. History District Pithoragarh, Government of Uttarakhand India
2. Puneeta, Singh, Bisht. Revisiting the Migration Trends in Uttarakhand. International journal of science and research, 2024. doi: 10.21275/sr24321004306
3. An Empirical Study on the Trend and Government Policies to mitigate the Rural Migration concerning Garhwal District (Uttarakhand). Journal of mountain research, 2022. doi: 10.51220/jmr.v17i1.3
4. Ishwar, Chandra, Awasthi, Balwant, Singh, Mehta. Forced Out-Migration from Hill Regions and Return Migration During the Pandemic: Evidence from Uttarakhand. The Indian journal of labour economics, 2020. doi: 10.1007/S41027-020-00291-W
5. Raiz Ahmed, Veer, Singh, Anita, Rudola, Gaurav. A Geographical Analysis of Rural Out-Migration and Its Impact on the Rural Landscape of Selected Villages in Garhwal District (Uttarakhand). Journal of mountain research, 2022. doi: 10.51220/jmr.v17i2.15